

जगदीश लाल नारंग बनाम कर निर्धारण प्राधिकारी, करनाल
और एक और (तुली, जे)

सिविल विविध

न्यायमूर्ति बाल राज तुली के स्मक्ष

जगदीश लाल नारंग, - याचिकाकर्ता बनाम

कर निर्धारण प्राधिकारी, करनाल और अन्य, प्रतिवादी।

1968 की सिविल रिट संख्या 3374।

21 जनवरी, 1970।

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948 का XLVI) - धारा 2 (ई), अनुसूची 'बी' प्रविष्टि संख्या 18 - भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 368 (12) - "माल" की परिभाषा - चाहे इसमें पशु, पक्षी, पशुधन और जीवित मुर्गी पालन शामिल हैं - 'खुरों पर मांस' की बिक्री - क्या बिक्री-कर से छूट दी गई है।

माना जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 366 (12) में 'माल' शब्द की परिभाषा संपूर्ण नहीं है। यह केवल यह बताता है कि 'माल' में सभी सामग्री, वस्तुएं और लेख शामिल हैं। यह चेतन चीजों को छोड़कर केवल निर्जीव चीजों तक ही सीमित नहीं है। जानवर और पक्षी चल संपत्ति हैं क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है और यह चोरी या चोरी का विषय भी हो सकता है। उनके मालिक व्यक्ति का पूरा नियंत्रण होता है और वह उन्हें किसी भी तरह से निपटा सकता है। पशु-पक्षी किसी भी व्यक्ति के कब्जे में किसी अन्य वस्तु या मूर्त वस्तु के रूप में चल संपत्ति का गठन करते हैं। 'माल' शब्द को केवल निर्जीव चीजों तक सीमित करने का कोई कारण नहीं है और इसलिए जानवर, पशुधन और जीवित मुर्गी, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ई) में दिए गए 'माल' शब्द की परिभाषा के भीतर आते हैं, और उनकी बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है। (पैरा 8)

आयोजित, कि 'खुरों पर मांस' का अर्थ है जीवित जानवर जो उनके मांस सामग्री के लिए खरीदे जाते हैं। मांस जानवर के वध के बाद बनाया जाता है या अस्तित्व में आता है और तब तक मांस को उसकी प्राकृतिक पैकिंग, त्वचा में बंद कर दिया जाता है, और इस तरह संरक्षित किया जाता है। टिन, बोतलों या डिब्बों में बेचे जाने वाले मांस को अधिनियम की अनुसूची 'बी' में प्रविष्टि संख्या 18 के तहत बिक्री कर के भुगतान से छूट नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संरक्षित रूप में मांस को छूट नहीं है। खुरों पर मांस भी संरक्षित मांस है, संरक्षण जानवर की त्वचा से युक्त प्राकृतिक कार्टन में है। इसलिए 'मीट ऑन हूफे' को अधिनियम की अनुसूची 'बी' में प्रविष्टि संख्या 18 के तहत बिक्री कर के उद्ग्रहण से छूट नहीं है। (पैरा 8 और 10)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए जिसमें प्रतिवादी संख्या 10 को निर्देश दिया गया हो। (घ) सरकार ने 6 अगस्त, 1968 को जस्ट किए गए लेखा बहियों को लौटाने के लिए एक आदेश दिया है और प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया है। मैं याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम के तहत कोई मूल्यांकन करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं।

भागीरथ दास, और एस। याचिकाकर्ता के लिए हिराजी, अधिवक्ता।

जे.एस. मलिक, एडवोकेट जनरल (हरियाणा) के एडवोकेट, उत्तरदाताओं के लिए।

जगदीश लाल नारंग बनाम कर निर्धारण प्राधिकारी, करनाल
और एक और (तुली, जे)

निर्णय

न्यायमूर्ति तुली—यह निर्णय 1968 की सीडब्ल्यू संख्या 3374, जगदीश लाल नारंग बनाम भारत संघ का निपटारा करेगा। निर्धारण प्राधिकरण, करनाल और अन्य, 1969 की सीडब्ल्यू संख्या 118-दफदार भगत सिंह एंड संस वी। संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, पंजाब, और अन्य, और 1969 के सीडब्ल्यू नंबर 166, मेसर्स तारा चंद एंड संस वी। संयुक्त आबकारी और कराधान आयुक्त, पंजाब, और अन्य, कानून के सामान्य प्रश्न इन सभी रिट याचिकाओं में उठते हैं।

1968 की सीडब्ल्यू संख्या 3374 में, याचिकाकर्ता जगदीश लाल नारंग ने कामा जिले के गांव कछवा में एक मुर्गी फार्म शुरू किया। 1958 में और 1964 में करनाल में उसी व्यवसाय को करना शुरू किया। उनका व्यवसाय अंडे, वध किए गए मुर्गी (मांस) और जीवित मुर्गी बेचना है। मामले में निर्धारण का बिंदु यह है कि क्या "जीवित मुर्गी" को पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) में दी गई "माल" की परिभाषा में शामिल किया गया है।

(2) 1969 की सिविल रिट संख्या 118 और 166 में याचिकाकर्ता ठेकेदार हैं जो सेना के अधिकारियों को खुरों पर मांस और मांस की आपूर्ति करते हैं। खुरों पर मांस का वास्तव में अर्थ है जीवित भेड़ और बकरियां जिन्हें सेना के प्राधिकारियों द्वारा उसमें मांस की मात्रा के आधार पर खरीदा जाता है अर्थात् भेड़ और बकरियों को तौला जाता है और कीमत का भुगतान पशु के वजन के 50 प्रतिशत प्रति किलो सहमत दर पर किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि भेड़ और बकरी जैसे जानवरों की बिक्री पर कोई बिक्री कर देय नहीं है और भले ही यह तर्क के लिए माना जाए कि इन जानवरों को "माल" की परिभाषा में शामिल किया गया है, जो 'बेचा जाता है, वास्तव में, और पार्टियों के बीच अनुबंध के अनुसार मांस है, जो बिक्री कर के भुगतान से मुक्त है, न कि जीवित भेड़ और बकरियों को।

(3) तीनों याचिकाओं में तय किया जाने वाला पहला बिंदु यह है कि क्या जीवित पक्षी और जानवर अधिनियम की धारा 2 (ई) में उस शब्द की परिभाषा के भीतर 'माल' हैं, जो निम्नानुसार है: -

"माल" का अर्थ है समाचार-पत्रों, कार्रवाई योग्य दावों के अलावा सभी प्रकार की चल संपत्ति, स्टॉक, 5, शेयर या प्रतिभूतियां।

(4) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का निवेदन यह है कि राज्य विधान मंडल के पास संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 54 के तहत माल की बिक्री और खरीद पर कर लगाने वाला कानून बनाने की शक्ति है, और माल, जिसकी बिक्री और खरीद कर के अधीन हो सकती है, वे ऐसे हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 (12) में "माल" शब्द की परिभाषा द्वारा कवर किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 366 (12) "माल" शब्द की एक विस्तृत परिभाषा नहीं देता है, लेकिन केवल एक समावेशी परिभाषा देता है। इस खंड के

जगदीश लाल नारंग बनाम कर निर्धारण प्राधिकारी, करनाल
और एक और (तुली, जे)

अनुसार, "माल" में सभी सामग्री, वस्तुएं और लेख शामिल हैं। इस परिभाषा से विद्वान वकील का निष्कर्ष है कि "माल" शब्द द्वारा जो कवर किया गया है वह निर्जीव संपत्ति है और चेतन प्राणी नहीं है। मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है

संबंधित विभिन्न अधिनियमों में "माल" शब्द की परिभाषाओं के लिए तक अन्य राज्यों का बिक्री कर। बिहार, केरल और मैसूर अधिनियमों में "माल" शब्द की परिभाषा में स्पष्ट रूप से पशुधन शामिल है, जबकि अन्य अधिनियमों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि राजस्थान अधिनियम में "माल" की परिभाषा में विशेष रूप से पशुधन का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि परिभाषा में शामिल है, राजस्थान सरकार द्वारा भैंसों, बछड़ों और बैलों आदि पर बिक्री कर लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। के एक विद्वान एकल न्यायाधीश वही केरल उच्च न्यायालय में आयोजित अब्राहम बहुत। सहायक बिक्री कर अधिकारी। अलवे, (1) -

"इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कैद में जानवर और पक्षी (बंदर, मिनाह और तोते; इन मामलों में) चल संपत्ति हैं, और इसलिए, वे "माल" हैं, क्योंकि यह शब्द केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 (डी) में परिभाषित किया गया है। इसलिए ऐसी चीजों की बिक्री उस अधिनियम के तहत कराधान के लिए उत्तरदायी है। यह तर्क कि चेतन चीजें संविधान के अनुच्छेद 366 (12) में "माल" की परिभाषा के भीतर नहीं आएंगी, याचिकाकर्ताओं को दूर तक नहीं ले जाती हैं, भले ही यह अच्छी तरह से स्थापित हो। यह मानते हुए कि यह सुस्थापित है, ऐसी चीजों की बिक्री सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 या सूची I की प्रविष्टि 92-A के अंतर्गत नहीं होगी। अतः यह सूची 1 की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत आएगा और ऐसी बिक्री पर कर लगाने का उपबंध करना संसद के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(5) वह मामला केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से संबंधित था न कि किसी राज्य अधिनियम से। इस मामले की विस्तार से जांच नहीं की गई कि क्या चेतन चीजें संविधान के अनुच्छेद 366 (12) में "माल" की परिभाषा के भीतर आती हैं। इसलिए, यह निर्णय बहुत मदद नहीं करता है।

(6) गोसरी डेयरी में केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ, वित्तिना बनाम केरल राज्य, (2) ने बिक्री कर अधिकारियों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता की सूखी गायों की बिक्री उसके व्यवसाय का हिस्सा थी, इसे बिक्री कर अधिनियम के अर्थ के भीतर एक डीलर का गठन किया, और उसके संबंध में कराधान के लिए देयता को आकर्षित किया। यह निर्णय भी बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि केरल बिक्री कर अधिनियम में "माल" की परिभाषा में पशुधन शामिल है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पूर्ण पीठ के विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष यह तर्क नहीं दिया गया था कि केरल अधिनियम में "माल" की परिभाषा

(1) एआईआर 1960 केरल 360.

(2) (1961) 12 एसटीसी 683।

संविधान के अनुच्छेद 366 (12) में दिए गए एक से परे चला गया और इसलिए, पशुधन को

"माल" शब्द में शामिल नहीं किया जा सकता है; और पशुधन की बिक्री या खरीद पर कर लगाने वाला कोई कानून राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 54 के तहत नहीं बनाया जा सकता है।

(8) जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, संविधान के अनुच्छेद 366(12) में "माल" शब्द की परिभाषा संपूर्ण नहीं है। यह केवल यह बताता है कि "माल" में सभी सामग्री, वस्तुएं और लेख शामिल हैं। ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि केवल ऐसी चीजें "माल" का गठन करती हैं ताकि एजुस्टेड जेनेरिस के सिद्धांत को लागू करते हुए यह माना जा सके कि केवल निर्जीव चीजें परिभाषा द्वारा कवर की जाती हैं और चेतन चीजें नहीं। यह किसी भी संदेह को स्वीकार नहीं करता है कि जानवर और पक्षी चल संपत्ति हैं, खरीदे और बेचे जा सकते हैं और चोरी या चोरी के विषय भी हो सकते हैं। उनके मालिक व्यक्ति का पूरा नियंत्रण होता है और वह उन्हें किसी भी तरह से निपटा सकता है। पशु-पक्षी उसकी चल संपत्ति के रूप में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसके कब्जे में कोई अन्य वस्तु या मूर्त वस्तु। इसलिए, मुझे "माल" शब्द को केवल निर्जीव चीजों तक सीमित रखने का कोई कारण नहीं मिलता है और यह मानता हूँ कि पशु, पशुधन और जीवित मुर्गी, अधिनियम की धारा 2 (ई) में दिए गए "माल" शब्द की परिभाषा के भीतर आते हैं और उनकी बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा 1969 के सिविल रिट 118 और 166 में जो बेचा गया था, वह 'खुरों पर मांस' था। यह एक प्रकार का मांस है, जो अपने प्राकृतिक आवरण, त्वचा में संरक्षित है, और चूंकि मांस "माल" है, इसलिए "खुरों पर मांस" को भी 'माल' माना जाना चाहिए, जिस पर बिक्री कर देय है जब तक कि अधिनियम की अनुसूची 'बी' में नंबर 18 पर प्रविष्टि के तहत छूट न दी जाए।

(9) मुझे यह भी नहीं पता कि 1969 के सिविल रिट संख्या 118 और 166 में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने दूसरा आरआरसबमिसियो में कोई भी प्रभाव डाला है कि उन्होंने मांस बेचा है, जो अधिनियम की अनुसूची 'बी' में नंबर 18 पर प्रविष्टि के आधार पर बिक्री कर के भुगतान से मुक्त है। टिन, बोतलों या डिब्बों में बेचे जाने को छोड़कर हर प्रकार के मांस, मछली और अंडे को बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दावा किया गया है कि ओटिशनर्स और सेना के अधिकारियों के बीच अनुबंध की शर्तों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि मांस कपड़े पहने हुए हो सकता है या खुरों पर हो सकता है। अनुबंध की उस शर्त के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने सेना के अधिकारियों को बकरियों या भेड़ों की आपूर्ति की, जिन्होंने उन्हें वांछित स्थानों तक पहुंचाया और याचिकाकर्ताओं को शीन में मांस के वजन के आधार पर कीमत का भुगतान किया गया।

बकरियां: कीमत के भुगतान के प्रयोजनों के लिए यह सहमति हुई थी कि बकरी या भेड़ के वजन का 5,0 प्रतिशत मांस के संदर्भ में कीमत के भुगतान के उपाय के रूप में लिया जाएगा, अर्थात्, प्रति किलो मांस की दर के आधार पर पशु के 50 प्रतिशत वजन के संबंध में कीमत देय थी। याचिकाकर्ताओं के इस दावे का प्रतिवादियों ने खंडन नहीं किया है। वास्तव में, इस दावे को स्वीकार कर लिया गया है। इस दावे के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सेना के अधिकारियों को केवल मांस बेचा जा रहा था, न कि भेड़ और बकरियों को। अपने तर्क के समर्थन में वह आंध्र प्रदेश सरकार बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के अपने आधिपत्य के फैसले का हवाला देते हैं। (3) जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां होती हैं -

"यह सच है कि व्यावसायिक लेनदेन में कार्य अनुबंधों को अक्सर सभी वाचाओं और शर्तों को निर्धारित करते हुए लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जाता है, और अनुबंधों के नियमों और घटनाओं को साक्ष्य और परिचर परिस्थितियों से इकट्ठा किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में सवाल पार्टियों के बीच सही समझौते के बारे में है और समझौते की शर्तों को सभी परिचर परिस्थितियों की समीक्षा से घटाया जाना चाहिए। लेकिन एक मूलभूत तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि माल के अभिन्न अंग या स्वतंत्र के रूप में माल के शीर्षक को पारित करने से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि माल बेचने के लिए सहमत थे, और कीमत बिक्री कर के लिए उत्तरदायी थी।

(10) इस टिप्पणी पर यह तर्क दिया गया कि समझौता मांस बेचने के लिए था, जो कि छूट प्राप्त माल है; न कि भेड़ और बकरियों की। भेड़ और बकरी के रूप में इन जानवरों के नाम पार्टियों को ज्ञात थे, लेकिन उन नामों का उपयोग करने के बजाय वाक्यांश खुरों पर मांस का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करने और जोर देने के लिए किया गया था कि अनुबंध का विषय मांस था न कि जीवित जानवर। निर्णय के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या "खुरों पर मांस" शब्द के रूप में - ■। याचिकाकर्ताओं द्वारा एड को बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई है। मांस जानवर के वध के बाद बनाया जाता है या अस्तित्व में आता है और तब तक जानवर का मांस उसकी प्राकृतिक पैकिंग, त्वचा में संलग्न होता है, और तब तक संरक्षित रहता है जब तक कि जानवर का वध नहीं किया जाता है। बेचे जाने वाले मांस को अधिनियम की अनुसूची 'बी' में प्रविष्टि संख्या 18 के तहत बिक्री के भुगतान से छूट नहीं है जिसके कारण

(3)(1965) 16 एसटीसी 240.

